



एक नजर

रवाई घाटी में अधिक बारिश से फसलें बर्बाद

उत्तरकाशी। सामान्य से अधिक हुई बारिश ने रवाई घाटी के किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सामान्य से ज़्यादा हुई बारिश ने न सिर्फ उनकी खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है, बल्कि आने वाली फसलों की बुआई पर भी असर डाला है। समस्या को लेकर किसानों में गहरी चिंता है। लाल धान की खेती करने वाले किसान नवीन गैरेला ने कहा कि इस साल धान की फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। वहीं सेब उत्पादक किसान रामप्रसाद,कपिल देव ने कहा कि भारी बारिश के कारण उनकी सेब की फसल को भी भारी क्षति पहुंची है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों को इस गंभीर समस्या को देखते हुए राज्य स्तरीय लघु सिंचाई सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष जगत सिंह चौहान ने केंद्रीय कृषि, कृषि कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने फसल खराब होने और समय पर बुआई न हो पाने के कारण किसानों को हुए नुकसान की जाँच की मांग की है। चौहान ने पत्र में बताया है कि भारी बारिश से धान, राजमा, सब्जियां और तिलहन जैसी खड़ी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। इसके अलावा, अगस्त में बोई जाने वाली डांडे की मटर,बीन और फ्रांसबीन जैसी फसलें भी किसान बारिश की वजह से बो नहीं पाए हैं। उन्होंने पत्र के माध्यम से आग्रह किया है कि किसानों को हुए नुकसान का सही मूल्यांकन कर उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। उन्होंने उम्मीद जताई है कि केंद्र सरकार इस मामले में सज्जन लेते हुए किसानों को राहत पहुंचाएगी।

पिथौरागढ़ में रसोई गैस के लिए मारामारी

पिथौरागढ़। मैदानी क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कों के बीते दिनों बंद रहने से सीमांत में रसोई गैस संकट गहरा गया है। आपूर्ति कम और मांग अधिक होने से गैस एंजेंसी के लिए उपभोक्ताओं को घेरलु सिलेंडर उपलब्ध करना मुश्किल हो गया है। नतीजन घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद भी लोग खाली सिलेंडर घर ले जाने को मजबूर हैं। जिला मुख्यालय में सितारागंज से रसोई गैस की सप्लाई होती है। वाहन डनफुपर मार्ग से होते हुए यहां आवाजाही करते हैं, लेकिन बीते करीब 11 दिनों से यह मार्ग पहले सभी वाहनों के लिए वर्तमान में भारी वाहनों के लिए बंद है। इससे रसोई गैस की सप्लाई लड़खड़ा गई है। वर्तमान में रसोई गैस के वाहन हल्द्वानी से यहां पहुंच रहे हैं, लेकिन रसोई गैस के सीमित वाहन पहुंचने से दिक्रत खड़ी हो गई है। बीते दिन शहर में केवल रसोई गैस के एक वाहन का वितरण हुआ। स्थानीय निमा ने बताया कि वह रसोई गैस सिलेंडर रिफिल करने को स्याती में पहुंची, लेकिन रसोई गैस खस होने का हवाला देकर उन्हें कल आने के लिए कहा गया। बुधवार को सुबह गैस के वाहन जिला मुख्यालय पहुंचे,वाहन पहुंचने की सूचना के बाद काफी संख्या में लोग सिलेंडर लेने के लिए वितरण केंद्र पहुंच गए। खाला में फंसे रसोई गैस के वाहन वाया देवीधुरा आए पिथौरागढ़(आरएनएस)। चंपावत के खाला में सड़कों बंद होने के बाद यहां रसोई गैस लेकर आ रहे करीब सात से आठ वाहन सड़क गए। तिलहटकरी गैस प्रबंधक मंजु षिट्ट ने बताया कि कई दिनों बाद भी सड़क नहीं खुली तो वाहन वापस लौटे और बाद में वाया देवीधुरा होते हुए यहां पहुंचे।

नेपाल में बवाल से सीमा पर हाई अलर्ट

पिथौरागढ़। नेपाल में विरोध प्रदर्शनों की स्थिति को देखते हुए भारत-नेपाल सीमा पर जवानों को हाई अलर्ट मोड में रखा गया है। सीमा पर एएसएसबी ने दो दुना संख्या में जवानों की तैनाती कर दी है जो सीमा में चेकिंग अभियान में जुटी है। नेपाल में हिंसा को देखते हुए एएसएसबी ने भारत-नेपाल सीमा पर अतिरिक्त संख्या में जवानों को तैनात कर दिया है।

एसएसबी के कमांडेंट आशीष कुमार के निर्देश पर झुलापुलों में राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है जो पल-पल की खबर से अधिकारियों को अपडेट करेंगे। एसएसबी पुलिस व नेपाल सशस्त्र बल के साथ समन्वय स्थापित कर कार्रवायों में जुटी है। सीमा पर राउंड-द-क्लॉक (24 घंटे) संयुक्त नाकाबंदी व चेकिंग अभियान किया जा रहा है।

चुनाव से पहले बिहार की बल्ले—बल्ले, मोदी सरकार ने खोल दिया पिटारा

7,616 करोड़ को रेल और रोड प्रोजेक्टों को मंजूरी

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने राज्य को दो बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 7,616 करोड़ रुपये की दो अहम योजनाओं को मंजूरी दी गई। इनमें से एक परियोजना बिहार, झारखंड और बंगाल को जोड़ने वाले रेलवे ट्रैक का दोहरीकरण है, जबकि दूसरी हाई-स्पीड हाईवे परियोजना है, जिससे पूर्वी बिहार की औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में राज्य को मिली 7,616 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को राजनीतिक नजरिए से भी देखा जा रहा है। रेल और सड़क दोनों योजनाएं न केवल रोजमर्रा की कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगी बल्कि रोजगार, औद्योगिक निवेश और धार्मिक पर्यटन को भी नई दिशा देंगी। ये प्रधानमंत्री मोदी के गति शक्ति मास्टर प्लान और आत्मनिर्भर भारत की सोच के साथ



चुनावी मैदान में विकास बनाम वादे की बहस को भी मजबूती देंगी। **भागलपुर—दुमका—रामपुरहाट रेल लाइन का होगा दोहरीकरण** मंत्रिमंडल ने 3,169 करोड़ रुपये की लागत से 177 किलोमीटर लंबी भागलपुर—दुमका—रामपुरहाट एक्स्ट्र रेल लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के तहत परिचालन आगम होगा, भीड़भाड़ कम होगी और 1.5 करोड़ टन अतिरिक्त माल को मजबूत कर दिया जाएगा। इस परियोजना से बिहार के बांका के साथ—साथ झारखंड के गोड्डा और दुमका जैसे महत्वकांक्षी जिलों को सीधा लाभ होगा।

करोड़ों के घोटाले में 17 नामी संस्थानों पर लटकी तलवार

देहरादून। उत्तराखंड में बहुचर्चित करोड़ों के छात्रवृत्ति घोटाले में जल्द बड़ी कार्रवाई हो सकती है। एसआइटी ने पांच जिलों की पुलिस को तीन दिन के भीतर अपने-अपने जिले में उजागर अनियमितताओं की जांच की रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार की छात्रवृत्ति योजना में उत्तराखंड में कुछ वर्ष पूर्व बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ था, जिसमें अब तक 17 नामी संस्थानों की भूमिका संदिग्ध पाई गई। अब इस मामले में एसआइटी की ओर से संदिग्ध संस्थान और व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई तय की जा सकती है।

पुलिस मुख्यालय में बुधवार को केंद्र सरकार की अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजनाओं में करोड़ों रुपये की अनियमितताओं के मामले में विशेष अन्वेषण दल (एसआइटी) की बैठक हुई। जिसमें पुलिस महानिरीक्षक (अपराध एवं कानून व्यवस्था) ने पांच जिलों देहरादून, हरिद्वार, उन्नावसिंह नगर, नैनीताल और रुद्रप्रयाग के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को तीन दिन के भीतर संदिग्ध शैक्षणिक संस्थानों और व्यक्तियों की



प्रारंभिक जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपने के कड़े निर्देश दिए हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं के लिए केंद्र सरकार की तीन प्रमुख छात्रवृत्ति योजनाएं संचालित की जाती हैं। प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना और मेरिट-कम-मॉन्स छात्रवृत्ति योजना।

ये योजनाएं राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर संचालित हैं और

छात्रवृत्ति की राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाती है। लेकिन, उत्तराखंड में वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे शैक्षणिक संस्थान और छात्र सामने आए, जिन्होंने फर्जीवाड़ा कर सरकारी धन का गवन किया। सूत्रों के मुताबिक, जांच में दोषी संस्थानों की मान्यता रद्द करने की तैयारी है। इसके साथ ही, धोखाधड़ी करने वाले व्यक्तियों, संस्थानों और बिचौलियों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जाएंगे।

92 संस्थानों में से 17 पर गहरा संदेह केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को 92 संदिग्ध शैक्षणिक संस्थानों की सूची जांच के लिए भेजी गई थी। शासन ने बीते 19 मई को जारी शासनादेश में सभी जिलाधिकारियों को जांच के आदेश दिए। जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि वे उपजिलाधिकारियों की

अध्यक्षता में जांच समितियां गठित करें और विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें। अब तक की जांच में 92 में से 17 संस्थान संदिग्ध पाए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज दी गई है। **एसआइटी की सख्त कार्रवाई की तैयारी** घोटाले की गंभीरता को देखते हुए गृह विभाग के बीते 24 जुलाई के शासनादेश तहत एक विशेष अन्वेषण दल (एसआइटी) का गठन किया गया। एसआइटी की अध्यक्षता पुलिस महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था कर रहे हैं। यह टीम छात्रवृत्ति योजनाओं में धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज, फर्जी दाखिलों और पैसों के दुरुपयोग जैसे मामलों की तह तक जाएगी। अब उक्त पांचों जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को संदिग्ध संस्थानों और व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट तीन दिन में सौंपने को कहा गया है। जांच में फर्जी दाखिले, बैंक खातों, दस्तावेजों, फीस रसीदों और छात्रवृत्ति आवेदनों की गहन पड़ताल की जा रही है।

बवाल के बाद सड़कों की सफाई शुरू

नई दिल्ली। नेपाल सरकार के विरुद्ध बड़ा आंदोलन शुरू कर देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफे के लिए मजबूर कर दिया। प्रदर्शकारियों ने ना सिर्फ देश संसद भवन और सुप्रीम कोर्ट को आग के हवाले कर दिया, बल्कि कई मंत्रियों के घरों पर भी धावा बोल दिया। बीते 48 घंटे में हालात बुरी तरह बिगड़ गए। अब नेपाली सेना ने सुरक्षा व्यवस्था को अपने हाथों में ले लिया है, जिसके बाद शांति की उम्मीद की जा रही है। इस बीच नेपाल के युवा बुधवार को एक बार फिर सड़कों पर उठे हैं, लेकिन इस बार वजह कुछ और है।युवा प्रदर्शन करने नहीं, बल्कि सफाई करने के लिए सड़कों पर उठे हैं। तमाम अनिश्चतताओं के बीच काठमांडू से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो उम्मीद की किरण जगा रहे हैं कि नेपाल में एक बार फिर शांति की स्थापना की जा सकती है। काठमांडू पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि किस तरह कुछ युवा, जिनमें से कई ने विशेष प्रदर्शनों में भी हिस्सा लिया था,

बेरीनाग में गुलदार दिखने से लोगों में दहशत

पिथौरागढ़। नगर में रात के समय गुलदार दिखने से स्थानीय लोगों में दहशत है। बुधवार को स्थानीय योगेश डांगी ने बताया कि बीते रात नगर के पीडब्ल्यूके के समीप बने आवासीय मकानों में दो गुलदार चहलकदमी करते हुए दिखे। जिसके बाद स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। पहले भी इस क्षेत्र में उन्हें गुलदार चहलकदमी करते हुए दिखे हैं। जिससे रात के समय लोगों का अकेले बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से क्षेत्र में पिंजा लगाने की मांग की है। वन क्षेत्राधिकारी चंदा मेहर ने बताया की वन विभाग के कर्मचारी क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है।

उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील राज्य : धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भारत सरकार की अन्तर मंत्रालयी टीम ने भेंट की



विकसित करने की दिशा कार्य करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष अत्यधिक वर्षा के कारण राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में काफी नुकसान हुआ है। जनहानि के साथ ही परिसंपत्तियों को भी अत्यधिक क्षति पहुंची है। कहा कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में बाढ़ल फटने व भूस्खलन की घटनाओं से जमीन का स्थाई नुकसान

को सगहनौर बताया। आपदा प्रभावितों के लिए राहत शिविरों में रहने व भोजन की समुचित व्यवस्था, मौके पर ही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था को भी केन्द्रीय टीम ने बेहतर बताया। केन्द्रीय टीम ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आपदा में मृतकों के परिजनों तथा जिनके घर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनको पांच लाख रुपये की तात्कालिक सहायता राशि दिए जाने से भी प्रभावितों को काफी राहत मिली है। राज्य में सभी गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण डाटा जिला प्रशासन के पास उपलब्ध होने एवं उनके स्वास्थ्य व सुशुभित प्रसव की व्यवस्था हेतु निरंतर संपर्क रखने की पहल की भी केन्द्रीय टीम ने सगहना की। टीम के सदस्यों ने कहा कि इस तरह की महत्वपूर्ण पहल को अन्य राज्यों में भी अपनाने के लिए अपना सुझाव प्रस्तुत करेगी।

12 सितंबर को उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करेंगे सीपी राधाकृष्णन

नई दिल्ली। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 12 सितंबर को शपथ लेंगे। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रैपेडी मूर्त शुक्लार को राधाकृष्णन को शपथ दिलाएगी। यह शपथ ग्रहण मंगलवार 12 सितंबर को राष्ट्रपति भवन में एक औपचारिक आयोजन में होगा। राधाकृष्णन ने भगतवार को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को हराकर जीत हासिल की। यह चुनाव पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखंड के 21 जुलाई को आननक इस्तीफे के बाद आयोजित किया गया था। एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन को मंगलवार को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया। उन्हें 452 वोट प्राप्त हुए, जबकि विपक्षी उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। राज्यसभा के महासचिव और निर्वाचन अधिकारी पीसी मोदी ने संयुक्त घोषित करते हुए बताया कि 781 सांसदों में से 767 ने मतदान किया, जिससे 98.2 प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ। इनमें 752 मत देव और 15 अश्वेथ थे, जिसके कारण प्रथम वरीयता के मतों के लिए आवश्यक बहुमत 377 रह गया। एनडीए को कामगो जी 427 सांसदों का समर्थन था, लेकिन बाईसआसीपी के 11 सांसदों ने भी राधाकृष्णन का साथ दिया। हिलसाक बात यह है कि एनडीए उम्मीदवार को अपेक्षा से 14 वोट अधिक मिले, जिससे विपक्षी खेमे में क्रैश—वांटिंग की अटकलें शुरू हो गईं।

लैरी एलिसन बने दुनिया के सबसे रईस अरबपति, टेस्ला के एलन मस्क को पछाड़ा



नई दिल्ली। दुनिया के सबसे रईस अरबपति अब टेस्ला के एलन मस्क नहीं बल्कि ओरेकल के को-फाउंडर लैरी एलिसन हैं। दरअसल, एलिसन की संपत्ति में भारी उछाल आया और उनकी कुल संपत्ति 395.7 अरब डॉलर हो गई है। इसी के साथ एलिसन दुनिया के अरबपतियों की रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गए। वहीं, टेस्ला के मालिक एलन मस्क दूसरे स्थान पर खिसक गए। बता दें कि एलन मस्क साल 2021 में पहली बार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने थे। वह लंबे समय तक शीर्ष पर रहे लेकिन बाईक ओरेकल के शेयरों में ऐतिहासिक तेजी के बाद देखी गई है। बता दें कि बुधवार को ओरेकल के शेयर 41% तक बढ़ गए, जो साल 1992 के बाद सबसे बड़ी वृद्धि है। ओरेकल का बाजार मूल्यांकन अब 947 अरब डॉलर हो गया है। यह तेजी इसलिए भी अहम है क्योंकि कंपनी का पूरा फोकस अपने

सबको 22 सितंबर का इंतजार

बाईक,कार ही नहीं गारमेट—फुटवियर से एसी—टीवी तक हो जाएंगे सस्ते



उत्पादों की बिज्ने में भारी कमी आई है। 22 सितंबर के बाद इन वस्तुओं की खरीदारी पर ग्राहकों को कम से कम

दी गई हैं। अब 2,500 रुपये से कम कीमत वाले सभी प्रकार के कपड़ों पर सिर्फ पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा। 21 सितंबर तक 1000 रुपये से कम कीमत वाले कपड़ों और जूतों पर 5% और उससे ज़्यादा कीमत वाले पर 12% जीएसटी लगेगा। जूतों पर भी इसी तरह जीएसटी लगेगा। दुकानदारों ने बताया कि 2,500 रुपये तक के कपड़ों की बिज्ने में 60% से अधिक हिस्सेदारी है। ऐसे में 22 सितंबर से पहले खरीदारी करने पर ग्राहकों को नुकसान क्यों होगा? हालांकि, वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा 6 सितंबर से अपने ग्राहकों को नई जीएसटी दर का लाभ दे रही है। दुकानदारों का कहना है कि कपड़ों और जूतों में ऐसा संभव नहीं है।

